

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(डॉ.सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

03 / 2024
29.01.2024

छीतर पुत्र गोदू जाति माली निवासी मालियो की झोपडिया तन मेहन्दवास तहसील व
जिला टोंक राज0

—अपीलांट

बनाम

तहसीलदार टोंक राज0

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार टोंक दिनांक 04.01.2024 मिसल नम्बर 631 / 2023

उपस्थिति : (1) श्री बाबूलाल गुसांरिया, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 21.02.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 04.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 740 रकबा 0.7587 है0 एवं खसरा नम्बर 741 रकबा 0.2529 है0 किस्म बजड-3 वाके ग्राम अमीनपुरा तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 240/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया है। अपीलांट के विरुद्ध तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा दुर्भावना पूर्वक गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलांट को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किये जाने बाबत हल्का पटवारी द्वारा कोई विश्वसनीय सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करना का अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलांट को उक्त आराजी से कभी बेदखल नहीं किया है। अपीलांट ने उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक में दावा उद्घोषणा, खातेदारी दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा (16/2012) पेश करने पर न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक ने अपने आदेश दिनांक 18.05.2015 से उक्त दावा को

जिला कलेक्टर

स्वीकार किया गया है, उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में होने के बाद भी अपीलान्त को उक्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्त को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 736 में से रकबा 1.0116 है 0 किस्म बजड-2 वाके ग्राम अमीनपुरा तहसील टोक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार टोक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्त स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की और से मदनलाल की तामील हुई है। अपीलान्त स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 740 रकबा 0.7587 है 0 व खसरा नम्बर 741 रकबा 0.2529 है 0 किस्म बजड-3 वाके ग्राम अमीनपुरा तहसील टोक पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं 0 508/2022 निर्णय दिनांक 21.12.2022 से भूमि से बेदखल किया गया है। अतिक्रमी बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोक का निर्णय दिनांक 04.01.2024 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. सीमा झा)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोक